श्याम सरन

श्याम सरन (जन्म 4 सितंबर 1946) एक भारतीय कैरियर राजनयिक हैं। वह 1970 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और भारत सरकार के विदेश सचिव बने। विदेश सचिव के रूप में नियुक्ति से पहले उन्होंने म्यांमार, इंडोनेशिया और नेपाल में भारत के राजदूत और मॉरीशस में उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया। विदेश सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने पर, उन्हें भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु मुद्दों के लिए प्रधान मंत्री का विशेष दूत नियुक्त किया गया और बाद में जलवायु परिवर्तन पर विशेष दूत और मुख्य वार्ताकार नियुक्त किया गया।

2015 तक, श्याम सरन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया - आर्थिक और व्यापार संबंधी मुद्दों पर अध्ययन में विशेषज्ञता वाला एक स्वायत्त थिंक टैंक। [1] वह नियमित रूप से राजनीति और विदेश नीति के मुद्दों पर टिप्पणी करते हैं और बोलते हैं और कई पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में योगदानकर्ता हैं।

2011 में, सिविल सेवा में उनके योगदान के सम्मान में , उन्हें भारत में तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान - पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

प्रारंभिक कैरियर

वह 1970 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और बाद में बीजिंग, टोक्यो और जिनेवा सहित दुनिया की कई राजधानियों में भारतीय राजनयिक मिशनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। विदेश सचिव के रूप में नियुक्ति से पहले , वह म्यांमार, इंडोनेशिया और नेपाल में भारत के राजदूत और मॉरीशस में उच्चायुक्त थे। विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में , उन्होंने आर्थिक प्रभाग और बहुपक्षीय आर्थिक प्रभाग का नेतृत्व किया और पूर्वी एशिया प्रभाग का भी नेतृत्व किया जो चीन और जापान के साथ संबंधों को संभालता है। 1991/92 में प्रधान मंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में, उन्होंने प्रधान मंत्री को विदेश नीति, परमाणु और रक्षा संबंधी मुद्दों पर सलाह दी। विदेश सचिव और बाद में परमाणु मुद्दों पर विशेष दूत के रूप में उन्होंने भारत-अमेरिका परमाणु समझौते में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

विदेश सचिव

चीन

विदेश सचिव के रूप में, उन्होंने सीमा मुद्दे पर भारत-चीन संयुक्त कार्य समूह की 15वीं बैठक के लिए मार्च 2005 में चीन का दौरा किया।

परमाणु हथियारों पर रुख

अप्रैल 2006 में, उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायक सचिव रिचर्ड बाउचर के सुझाव के बाद कि भारत अपने न्यूनतम विश्वसनीय परमाणु-निरोधक को "आगे परिभाषित" करे, भारत का कोई दायित्व नहीं है। अपने कार्यकाल के दौरान, सरन ने अमेरिका-भारत नागरिक परमाणु समझौते पर बातचीत में मदद की । दिसंबर 2012 में, उन्होंने एक शोध लेख लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार का विस्तार इस बार भारत को रोकने के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान पर संभावित अमेरिकी हमले को रोकने के लिए किया गया है।

बाद का करियर

यद्यपि प्रधान मंत्री कार्यालय विदेश सचिव के रूप में उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए तैयार था, जब वह सितंबर 2006 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, अंब। सरन सेवानिवृत्त हो गए। वह परमाणु मुद्दों में विशेषज्ञता वाले प्रधान मंत्री के सलाहकार थे , साथ ही जलवायु परिवर्तन पर भारतीय दूत भी थे। उन्होंने 19 फरवरी 2010 को पद छोड़ दिया। वह *विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली* (आरआईएस) थिंकटैंक के अध्यक्ष और नई दिल्ली में *सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च* में एक वरिष्ठ फेलो थे। वह विश्व विकास मंच के सलाहकार बोर्ड में भी हैं , जो एक आगामी मंच है जिसका उद्देश्य नागरिक समूहों , विकास संगठनों, व्यवसायों और सरकारों को साक्ष्य-आधारित राजनीतिक रूप से कार्रवाई योग्य मार्गदर्शन का उत्पादन करने और अधिक मूल्य अनलॉक करने के लिए एक आम मंच पर लाना है। मानव उद्यम. इसके अतिरिक्त, सरन ग्लोबल पैनल फाउंडेशन के सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं , जो एक सम्मानित एनजीओ है जो दुनिया भर के संकटग्रस्त क्षेत्रों में पर्दे के पीछे से काम करता है।